अध्याय 1

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों का वित्तीय निष्पादन

1.1 प्रस्तावना

इस प्रतिवेदन में सरकारी कम्पनियों, सांविधिक निगमों और मानी गई सरकारी कम्पनियों के वित्तीय निष्पादन प्रस्तुत किए गए हैं। शब्द केन्द्रीय सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) में कम्पनी के अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत गठित सरकारी स्वामित्व कम्पनियाँ और संसद की संविधियों के अन्तर्गत गठित सांविधिक निगम सम्मिलित हैं जिनकी लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) को सौंपी गई है।

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में एक **सरकारी कम्पनी** की परिभाषा ऐसी कम्पनी के रूप में दी गयी है जिसमें प्रदत्त शेयर पूंजी का कम से कम इक्यावन प्रतिशत केन्द्रीय सरकार, अथवा किसी राज्य सरकार या सरकारों या आंशिक रूप से केन्द्रीय सरकार द्वारा तथा आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा धारित हो और इसमें वह कम्पनी भी शामिल है जो इस प्रकार से परिभाषित कम्पनी की सहायक हो। इसके अतिरिक्त, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 बी के अन्तर्गत आने वाली कम्पनियां भी इस प्रतिवेदन में **मानी गई सरकारी कम्पनियों** के रूप में संदर्भित की गई हैं। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार संसद के विशेष नियमों के अधीन निगमों की स्थापना करती है जिन्हें **सांविधिक निगमों** के रूप में संदर्भित किया गया है।

सरकारी कम्पनियां

एक कम्पनी जिसमें प्रदत्त शेयर पूंजी का कम से कम 51 प्रतिशत केन्द्रीय सरकार, अथवा किसी एक या अधिक राज्य सरकारों या आंशिक रूप से केन्द्रीय सरकार द्वारा तथा आंशिक रूप से राज्य सरकार (रों) द्वारा धारित हो और इसमें वह कम्पनी भी शामिल है जो सरकारी कम्पनी की सहायक हो।

1.1.1 अधिदेश

सरकारी कम्पनियों और मानी गई सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा सीएजी के (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के प्रावधानों तथा उनके अधीन बनाए गए विनियमों के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा की जाती है। कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत सीएजी कम्पनियों के लिए लेखापरीक्षकों के रूप में सनदी लेखाकार (सांविधिक लेखापरीक्षक) की नियुक्ति करता है और अनुपूरक लेखापरीक्षा करने के अतिरिक्त वे निर्देश देता है जिनके अनुसार लेखापरीक्षा

की जाती है। कुछ सांविधिक निगमों को अधिशासित करने वाली संविधियों में उनके लेखाओं की सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा की अपेक्षा की गई है।

भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय निर्यात-आयात बैंक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक तथा राष्ट्रीय आवास बैंक को अधिशासित करने वाले अधिनियमों में वे प्रावधान निहित हैं जिनके द्वारा केन्द्र सरकार इन निगमों के लेखाओं की जांच करने और उन पर रिपोर्ट करने के लिए किसी भी समय सीएजी को लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त कर सकती है। 2012-13 के दौरान ऐसी कोई नियुक्ति नहीं की गई थी।

1.1.2 इस प्रतिवेदन में क्या है

इस प्रतिवेदन में सरकारी कम्पनियों और निगमों द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता तथा कम्पनियों तथा निगमों के लेखाओं से प्रकट उनके निष्पादन के मूल्यांकन की समग्र स्थिति को दर्शाया गया है।

लेखाओं के संशोधन तथा वर्ष 2012-13 (अथवा पिछले वर्षों जिन्हें चालू वर्ष के दौरान अन्तिम रूप दिया गया हो) के लिए सीएजी द्वारा की गई केन्द्र सरकारी कम्पनियों की वित्तीय विवरणियों की अनुपूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप की गई महत्वपूर्ण टिप्पणियों, तथा सीपीएसईज़ की वित्तीय विवरणियों का प्रमाणीकरण करते समय सांविधिक लेखापरीक्षा द्वारा सूचित महत्वपूर्ण निष्कर्षों का प्रभाव इस प्रतिवेदन में दिया गया है। जहां सीएजी ही एकमात्र लेखापरीक्षक है, वहां इस प्रतिवेदन में सांविधिक निगमों की वित्तीय विवरणियों पर सीएजी द्वारा जारी टिप्पणियों का प्रभाव भी निहित है। इसके अतिरिक्त, इस प्रतिवेदन में कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3) (क) के अन्तर्गत सीएजी द्वारा उन्हें जारी निदेशों के अनुपालन में सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों का सार भी दिया गया है।

प्रतिवेदन में कारपोरेट अभिशासन और कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के सीपीएसईज़ द्वारा पालन का भी वर्णन किया गया है।

1.1.3 सीपीएसईज़ और मानी गई सरकारी कम्पनियों की संख्या

31 मार्च 2013 को, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत 525 सीपीएसईज और मानी गई सरकारी कम्पनियाँ थी। इनमें 358 सरकारी कम्पनियां, 6 सांविधिक निगम और 161 मानी गई सरकारी कम्पनियां शामिल थी। इस प्रतिवेदन में समग्र कवरेज तथा इन सीपीएसईज़ का स्वरूप निम्निलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

• सरकारी कम्पनियाँ	358
• मानी गई सरकारी कम्पनियां	161
• सांविधिक निगम	6
• कुल सीपीएसईज़	525

सीपीएसई का स्परूप	सीपीएसईज की कुल संख्या	प्रतिवेदन में शामिल सीपीएसईज की संख्या				प्रतिवेदन में शामिल न की गई सीपीएसईज़ की संख्या
		नवीनतम आंकड़े 2012-13	पहले के आंकड़े		जोड़	
			2011-12	2010-11		
सरकारी कम्पनियां	358	306	14	1	321	37
सांविधिक निगम	6	6	0	0	6	0
कुल कम्पनियां/निगम	364	312	14	1	327	37
मानी गई सरकारी कम्पनियां	161	130	6	1	137	24
जोड़	525	442	20	2	464	61

नई/बन्द सरकारी कम्पनियों/मानी गई सरकारी कम्पनियों के विवरण **परिशिष्ट I** में दिए गए हैं।तथापि, इस प्रतिवेदन में 61 कम्पनियों (24 मानी गई सरकारी कम्पनियों सहित) जिनके लेखे तीन वर्षों या उससे अधिक के लिए बकाया में थे अथवा समाप्त/परिसमापन के अन्तर्गत थे अथवा पहले लेखे प्राप्त नहीं हुए थे अथवा पहले लेखे देय नहीं थे, को शामिल नहीं किया गया है। इन कम्पनियों को दो सितारों (**) के द्वारा **परिशिष्ट II** में दर्शाया गया है।

सीपीएसईज़ का आशुचित्र

(सरकारी कम्पनियाँ और सांविधिक निगम)

सीपीएसईज़ की संख्या	364
इस अध्याय में शामिल सीपीएसईज़	327
प्रदत्त पूंजी (327 सीपीएसईज़)	₹ 2,89,455 करोड़
दीर्घकालिन कर्ज़े (327 सीपीएसईज़)	₹ 7,18,577 करोड़
बाज़ार पूंजीकरण (44 सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियां)	₹ 11,10,382 करोड़
निवल लाभ (182 सीपीएसईज़)	₹ 1,48,142 करोड़
निवल हानि (124 सीपीएसईज़)	₹ 79,699 करोड़
घोषित लाभांश (107 सीपीएसईज़)	₹ 49,929 करोड़
उत्पादन का मूल्य (327 सीपीएसईज़)	₹ 12,15,187 करोड़
कुल परिसम्पत्तियां	₹ 29,45,185 करोड़
निवल धन (327 सीपीएसईज़)	₹ 10,75,057 करोड़

1.2 सरकारी कम्पनियों एवं निगमों में निवेश

2012-13 के अंत में 327 सरकारी कम्पनियों एवं निगमों में इक्विटी निवेश और कर्ज़ की सीमा निम्नलिखित तालिका में दी गई हैं। कुछ सरकारी कम्पनियों तथा निगमों ने भी इन सीपीएसईज में निवेश किया था। विवरण नीचे दिये गये हैं:

(₹ करोड़ में)

स्त्रोत	31 मार्च 2013 को			31 मार्च 2012 को		
	इक्विटी	दीर्घ कालीन कर्ज़ें	जोड़	इक्विटी	दीर्घ कालीन कर्ज़ें	जोड़
1.केन्द्रीय सरकार	2,25,037	50,437	2,75,474	2,05,385	53,277	2,58,662
2.केन्द्रीय सरकार की कम्पनियां/निगम	27,413	23,933	51,346	17,322	29,145	46,467
3.राज्य सरकारें/राज्य सरकार की कम्पनियां/निगम	18,490	5,771	24,261	16,282	4,801	21,083
4.वित्तीय संस्थाएं/अन्य	18,515	6,38,436	6,56,951	15,320	5,53,350	5,68,670
जोड़	**2,89,455**	**7,18,577**	**1,00,8032**	**2,54,309**	**6,40,573**	**8,94,882**
कुल के प्रति केन्द्रीय सरकार की प्रतिशतता	**77.75**	**7.02**	**27.33**	**80.76**	**8.32**	**28.90**

भारत सरकार, राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय/राज्य सरकारी कम्पनियों तथा निगमों द्वारा केन्द्रीय सरकारी कम्पनियों में धारित इक्विटी तथा दिए गए कर्ज़ों के मंत्रालय/विभाग वार विवरण **परिशिष्ट III** में दिए गए हैं।

1.2.1 इक्विटी निवेश

2012-13 के दौरान, इन सरकारी कम्पनियों तथा निगमों के इक्विटी में निवेश में ₹ 35,146 करोड़ की निवल वृद्धि दर्ज हुई। भारत सरकार का निवेश सीपीएसईज़ के इक्विटी में 2012-13 में ₹ 19,652 करोड़ तक बढ़ गया।

भारत सरकार का निवेश सीपीएसईज के इक्विटी मे 2012-13 में ₹ 19,652 करोड़ तक बढ़ गया।

सरकारी कम्पनियों एवं निगमों में इक्विटी निवेश

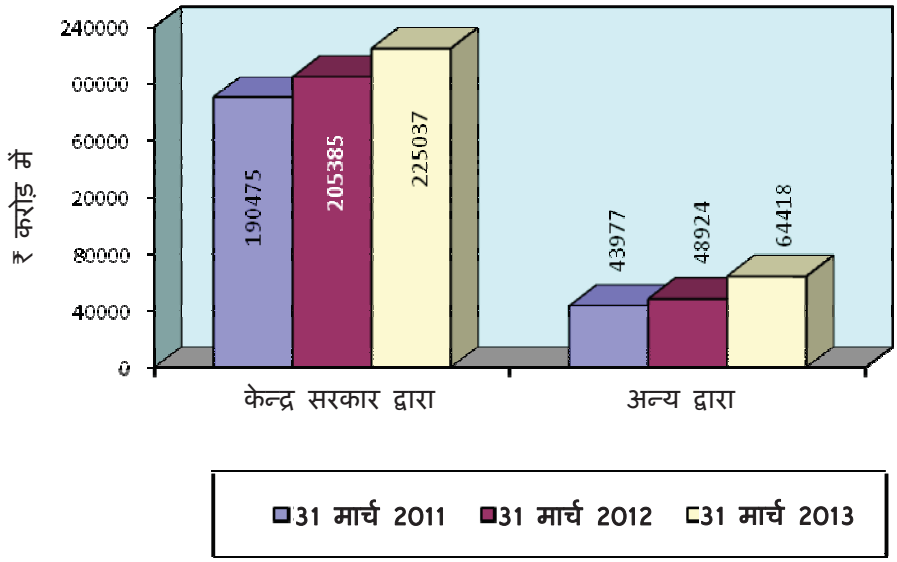

सीपीएसईज़ की प्रदत्त पूंजी में 2012-13 के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा किए गए महत्वपूर्ण निवेश के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

सीपीएसईज का नाम	मंत्रालय का नाम	राशि (₹ करोड़ में)
सांविधिक निगम		
नेशनल हाईवेज़ अथॉरिटी आफ इण्डिया	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग	15,856
सरकारी कम्पनियां		
डेडिकेटड फ्रेट कोरिडोर कारपोरेशन लिमिटेड	रेलवे	1,543
चैन्नई मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड	शहरी विकास	1,035
दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड	शहरी विकास	780
अन्य		438
जोड़		**19,652**

❖ वर्ष 2012-13 के दौरान नौ कम्पनियो ने ₹ 896 करोड़ की राशि के पूर्णत: प्रदत्त बोनस शेयर जारी किए जो निम्नानुसार हैं:

क्रम सं.	कम्पनी का नाम	राशि (₹ करोड़ में)
1	भारत पैट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड	362
2	ऑयल इंडिया लिमिटेड	361
3	राइट्स लिमिटेड	60
4	ओरियंटल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड	50
5	पीईसी लिमिटेड	40
6	इरकॉन इन्टरनेशनल लिमिटेड	10
7	एमएसटीसी लिमिटेड	7
8	डब्ल्यूएपीसीओएस (इंडिया) लिमिटेड	5
9	एड्यूकेशनल कन्सलटेंट्स इंडिया लिमिटेड	1
जोड		**896**

❖ वर्ष 2012-13 के दौरान, भारत सरकार ने विनिवेश पर ₹ 30,000 करोड़ की बजटीय प्राप्ति के प्रति ₹ 23,956 करोड़ की उगाही की। विनिवेश कार्यवाहियाँ निम्नलिखित दो सीपीएसईज के संबंध में इसके शेयरों के भाग की बिक्री से थीं।

क्रम सं.	सीपीएसईज का नाम	विनिवेशित शेयरों की प्रतिशतता	शेयरों का अंकित मूल्य (₹ करोड में)	सरकार द्वारा उगाही की गई राशि (₹ करोड में)
1	नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड	10.00	12.00	125
2	हिन्दुस्तान कोपर लिमिटेड	5.58	25.80	807
3	नेशनल मिनरल डिवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	10.00	39.65	5,973
4	ऑयल इंडिया लिमिटेड	10.00	60.11	3,141
5	एनटीपीसी लिमिटेड	9.50	783.26	11,457
6	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फार्टिलाइज़रस लिमिटेड	12.50	68.95	310
7	नेशनल एल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड	6.09	78.47	628
8	स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	5.82	240.40	1,515
जोड				**23,956**

इसके अतिरिक्त ₹ 1,432.24 करोड़ अधिमान शेयरों के विमोचन के कारण प्राप्त हुए थे जैसा कि नीचे दिया गया है:

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	राशि (₹ करोड़ में)
1	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	1,380.50
2	कोचीन शिर्पयार्ड लिमिटेड	39.14
3	मेकॉन लिमिटेड	12.60
	जोड	**1,432.24**

1.2.2 सरकारी कम्पनियों और निगमों को दिए गए कर्ज़

2012-13 के दौरान सरकारी कम्पनियों और निगमों को दिए गए दीर्घकालीन कर्ज़ों ने ₹ 78,005 करोड़ की निवल वृद्धि दर्ज की।

सरकारी कम्पनियों और निगमों को दिए गए बकाया दीर्घकालीन कर्ज
(₹ करोड़ में)

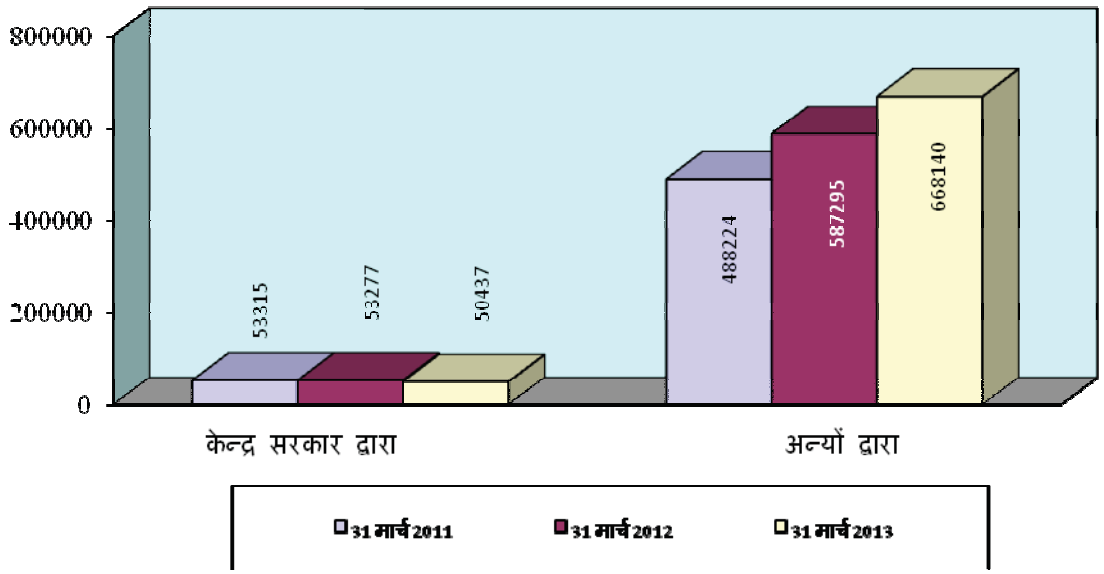

❖ 31 मार्च 2013 को सभी स्त्रोतों से 327 कम्पनियों/निगमों में बकाया कुल दीर्घकालीन कर्ज़े ₹ 7,18,577 करोड़ के थे। 2012-13 के दौरान उनके दीर्घकालीन कर्ज़ों के प्रति कुल परिसम्पत्तियों की धनात्मक तथा ऋणात्मक कवरेज का विश्लेषण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

	धनात्मक कवरेज				ऋणात्मक कवरेज			
	सीपीएसई की संख्या	दीर्घावधि कर्ज़	परिसम्पत्तियां	कर्जो के प्रति परिसम्पत्तियां की प्रतिशतता	सीपीएसई की संख्या	दीर्घावधि कर्ज़	परिसम्पत्तियां	कर्जो के प्रति परिसम्पत्तियों की प्रतिशतता
		(₹ करोड़ में)				(₹ करोड़ में)		
सांविधिक निगम	3	41,657	1,89,227	454.25				
सूचीबद्ध कम्पनियां	31	4,42,617	13,66,437	308.72	1	4,460	399	8.95
असूचीबद्ध कम्पनिया	102	2,16,223	6,65,156	307.62	23	13,619	1,922	14.11
कुल	**136**	**7,00,497**	**22,20,820**		**24**	**18,079**	**2,321**	

1 सूचीबद्ध कम्पनी सहित 24 सीपीएसईज़ के उनकी कुल परिसम्पत्तियों की तुलना में अधिक कर्ज थे। वहाँ 167 सीपीएसई (3 सांविधिक निगम सहित) थीं जिनके ऊपर कोई दीर्घावधि कर्ज नहीं था।

❖ ब्याज कवरेज अनुपात का प्रयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि एक कम्पनी कितनी आसानी से बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान कर सकती है और इसकी गणना उसी अवधि के ब्याज के खर्चों को ब्याज एवं कर से पूर्व कम्पनी की आय (ईबीआईटी) से भाग करके की जाती है। जितना कम अनुपात होता है, उतना ही अधिक कम्पनी पर ऋण खर्च का भार होता है। 1 से नीचे ब्याज कवरेज अनुपात यह दर्शाता है कि ब्याज खर्च को पूरा करने के लिए कम्पनी पर्याप्त राजस्व का सृजन नहीं कर रही है। 2010-11 से 2012-13 की अवधि के लिए धनात्मक तथा ऋणात्मक ब्याज कवरेज अनुपात के विवरण का सार नीचे दिया गया है:

वर्ष	ब्याज	ब्याज और कर से पूर्व आय (ईबीआईटी)	सीपीएसई* की संख्या	1 से अधिक ब्याज कवर अनुपात वाले सीपीएसईज़ की सं.	1 से कम ब्याज कवर अनुपात वाले सीपीएसइज़ की सं.
	(₹ करोड़ में)				
सांविधिक निगम					
2010-11	3,813	5,033	4	4	0
2011-12	6,143	6,586	4	4	0
2012-13	1,548	3,198	3	2	1
सूचीबद्ध सरकारी सम्पनियां					
2010-11	24,021	97,756	32	26	6
2011-12	33,285	98,910	34	26	8
2012-13	39,771	1,10,677	32	20	12
असूचीबद्ध सरकारी कम्पनियां					
2010-11	13,758	30,267	129	71	58
2011-12	15,444	30,022	124	68	56
2012-13	16,242	46,068	124	56	68

यह देखा गया था कि सांविधिक निगमों, सूचीबद्ध के साथ-साथ असूचीबद्ध सरकारी कम्पनियों के मामले में एक से अधिक ब्याज कवरेज अनुपात वाली सीपीएसईज़ की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में 2012-13 के दौरान घट गई थी।

1.2.3 मानी गई सरकारी कम्पनियों में निवेश

केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों द्वारा तथा उनके द्वारा नियंत्रित कम्पनियों और निगमों द्वारा निवेशित पूंजी 137 मानी गई सरकारी कम्पनियों में निम्न प्रकार से थी।

* उन सीपीएसईज़ को छोडकर जिनकी ब्याज पर कोई देयता नहीं है।

मानी गई सरकारी कम्पनियों में शेयर पूंजी की संरचना

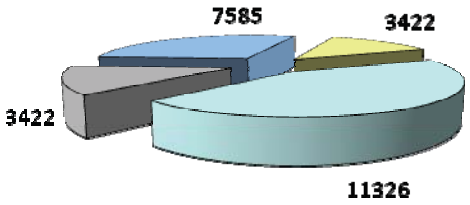

वित्तीय संस्थाएं एवं बैंक - ₹ 7,585 करोड़
अन्य - ₹ 3,422 करोड
केन्द्र सरकार, केन्द्र सरकारी कम्पनियां एवं निगम - ₹ 11,326 करोड़
राज्य सरकार, राज्य सरकार कम्पनियां एवं निगम - ₹ 3,422 करोड़

31 मार्च 2013 को 137 मानी गई सरकारी कम्पनियों में इक्विटी ₹ 25,755 करोड़ थी । भारत सरकार, राज्य सरकारों, कम्पनियों तथा निगमों द्वारा अंशदान के विवरण ***परिशिष्ट IV*** में दिए गए हैं। इन कम्पनियों में इक्विटी ₹ 5,807 करोड़ तक बढ़ गई अर्थात 2011-12 में ₹ 19,948 करोड़ से बढ़ कर 2012-13 में ₹ 25,755 करोड़ हो गई।

1.2.4 सरकारी कम्पनियों में इक्विटी निवेश का बाज़ार पूंजीकरण

बाज़ार पूंजीकरण पब्लिकली ट्रेडेड कम्पनी के बकाया शेयरों के बाज़ार मूल्य के आकार का माप है। 59 सरकारी कम्पनियों के शेयर भारत के विभिन्न स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध किए गए थे जिनमें 46 सरकारी कम्पनियां, सरकारी कम्पनियों की 5 सहायक कम्पनियां और 8* मानी गई सरकारी कम्पनियां शामिल हैं।

❖ 46 सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियों के संबंध में, 2012-13 के दौरान 41 कम्पनियों के शेयरों में ट्रेडिंग† हुई थी। नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन के शेयरों को अप्रैल 2012 में सूचीबद्ध किया गया था और उसे वर्ष-वार तुलना के लिए सम्मिलित नहीं किया गया है। सरकारी

---

* 1 इन्डबैंक हाउसिंग लिमिटेड, 2 इन्डबैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विसेस लिमिटेड, 3 पीएनबी गिल्टस लिमिटेड, 4 दी बिसरा स्टोन लाइम कम्पनी लिमिटेड, 5 उडीसा मिनरल्स डिवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड, 6 तमिलनाडु टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड, 7 टूरिज़्म फाइनेंस कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड और 8 आईएफसीआई लिमिटेड

† 2012-13 के दौरान (1) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड (2) हिन्दुस्तान फोटोफिल्मस (मैन्युफैक्चरिंग) कम्पनी लिमिटेड (3) इरकान इन्टरनेशनल लिमिटेड (4) इंडिया टूरिजम डेवेलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड एंव (5) केआईओसीएल लिमिटेड के शेयरों की ट्रेडिंग नहीं हुई थी।

कम्पनियों की 5 सहायक कम्पनियों के संबंध में वर्ष के दौरान 4 में ट्रेडिंग हुआ था और एक कम्पनी[+] के शेयर का ट्रेडिंग नहीं हुआ था।

- 44 सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियों में शेयरों का कुल बाज़ार मूल्य 31 मार्च 2013 तक ₹ 11,10,382 करोड़ थी। 31 मार्च 2013 तक 40 सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियों (4 सहायक कम्पनियों को छोडकर) के शेयरों का बाजार मूल्य ₹ 10,98,881 करोड़ था जिनमें से भारत सरकार द्वारा धारित शेयरों का बाजार मूल्य ₹ 8,30,913 करोड़ तक था। शेयरों का कुल बाजार मूल्य 31 मार्च 2013 की तुलना में 31 मार्च 2013 तक ₹ 1,42,041 करोड़ (12.9 प्रतिशत) तक घट गया था। विवरण **परिशिष्ट V-क** में दर्शाए गए हैं। इस अवधि के दौरान, बीएसई सेंसेक्स 17,404.20 (31.03.2012 को) से बढ़कर 18,835.77 (31.03.2013) हो गया, 8.23 प्रतिशत वृद्धि। तथापि, सीपीएसई इंडेक्स 7,311.47 (31.03.2012 को) से घटकर 6,481.16 (31.03.2013 को) हो गया जो 11.4 प्रतिशत की कमी दर्शाता है।
- 31 मार्च 2013 तक 4 सरकारी सहायक कम्पनियों के शेयरों का बाजार मूल्य, जिन शेयरों की ट्रेडिंग 2012-13 के दौरान हुई थी, ₹ 11,501 करोड़ रहा था। 31 मार्च 2012 की तुलना में 31 मार्च 2013 तक सरकारी कम्पनियों द्वारा 4 सरकारी सहायक कम्पनियों में धारित शेयरों का कुल बाजार मूल्य घट कर ₹ 2,999.83 करोड़ तक हो गया था। विवरण **परिशिष्ट V-ख** में दर्शाया गया है।
- 31 मार्च 2013 को अधिकतम बाज़ार पूंजीकरण वाली 10 टॉप पीएसईज़ नीचे दर्शाई गई हैं:

क्रम सं.	पीएसई का नाम	बाजार पूंजीकरण (₹ करोड़ में)
1	ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड	2,66,546
2	कोल इण्डिया लिमिटेड	1,95,270
3	एनटीपीसी लिमिटेड	1,17,086
4	इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड	68,335
5	नेशनल मिनरल डेवेलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड	54,535
6	पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	49,052
7	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	43,310
8	गेल (इण्डिया) लिमिटेड	40,483
9	ऑयल इण्डिया लिमिटेड	30,733
10	भारत पैट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड	27,343

[+] 2012-13 के दौरान ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के शेयरों की टैडिंग नहीं हुई थी।

11 सीपीएसईज़ में बाजार पूंजीकरण में वृद्धि हुई और अन्य 29 सीपीएसईज़ में कमी हुई। बाज़ार पूंजीकरण में महत्वपूर्ण कमी वाले सीपीएसईज़ नीचे दिये गयें है:

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	पीएसई का नाम	31.3.2012 को बाज़ार पूंजीकरण	31.3.2013 को बाज़ार पूंजीकरण	अंतर
1	एमएमटीसी लिमिटेड	78,345	19,925	58,420
2	कोल इंडिया लिमिटेड	2,16,714	1,95,270	21,444
3	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	62,891	43,310	19,581
4	एनटीपीसी लिमिटेड	1,34,154	1,17,086	17,068
5	हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड	24,750	8,577	16,173
6	स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	38,846	25,754	13,092
7	नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	63,872	54,535	9,337
8	गेल (इंडिया) लिमिटेड	47,562	40,483	7,079
9	नेशनल एल्यूमूनियम कंपनी लिमिटेड	14,097	8,544	5,553
10	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	8,558	5,207	3,351

1.3 सरकारी कम्पनियों और निगमों में निवेश पर प्रतिफल

327 सरकारी कम्पनियों और निगमों में 2010-11 से 2012-13 के दौरान लगाई गई निवल सम्पत्ति और पूंजी पर प्रतिफल **परिशिष्ट VI** में दर्शाया गया है। लाभ कमाने वाली सरकारी कम्पनियों और निगमों की संख्या 2011-12 में 191 (₹ 1,36,770 करोड़) से घट कर 2012-13 में 182 (₹ 1,48,142 करोड़) हो गई।

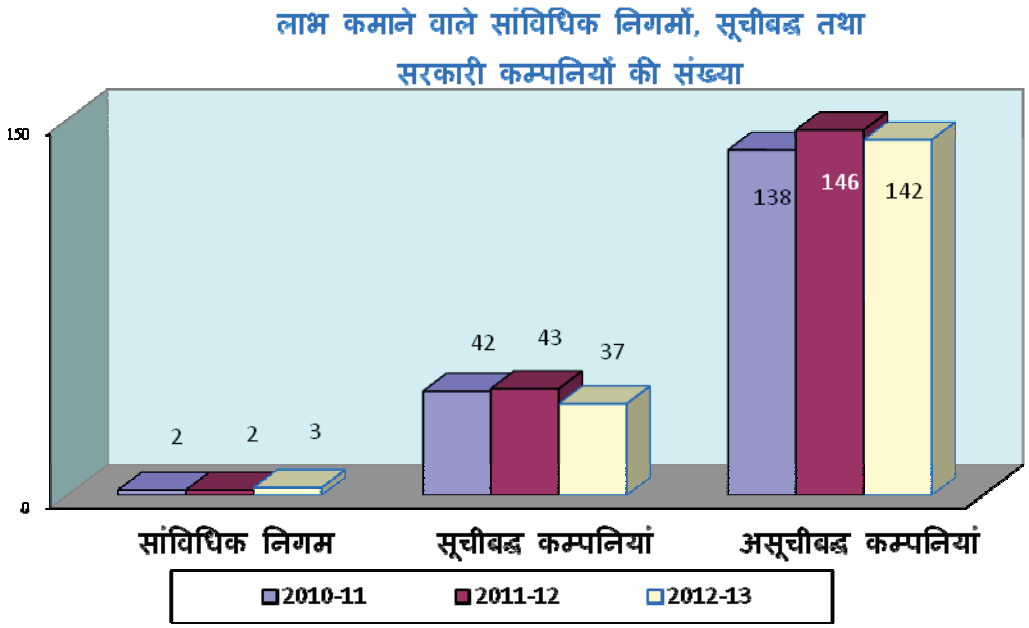

वर्ष 2012-13 के दौरान अधिकतम लाभ देने वाले क्षेत्रों के विवरण का सार नीचे दिया गया है:

क्षेत्र	लाभ कमाने वाले सीवीएसईज़ की संख्या	अर्जित निवल लाभ (₹ करोड़ में)	कुल सीपीएसई लाभ के प्रति लाभ की प्रतिशतता
1. पेट्रोलियम			
सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियां	6	37,090	25.04
असूचीबद्ध सरकारी कम्पनियां	4	2,816	1.9
जोड़	10	39,906	26.94
2. कोयला एवं लिग्नाईट			
सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियां	2	11,254	7.60
असूचीबद्ध सरकारी कम्पनियां	7	16,584	11.19
जोड़	9	27,838	18.79
3. विद्युत			
सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियां	4	20,253	13.67
सांविधिक निगम	1	392	0.26
असूचीबद्ध सरकारी कम्पनियां	13	3,592	2.42
जोड़	18	24,237	16.36
जोड़ (1) to (3)	**37**	**91,981**	**62.09**

182 सीपीएसईज़ द्वारा अर्जित कुल लाभ में से 62 प्रतिशत (₹ 91,981 करोड़) इन तीन क्षेत्रों में 37 सीपीएसईज द्वारा दिया गया था।

2012-13 की टॉप दस लाभ कमाने वाली सीपीएसईज़ निम्नलिखित हैं:

क्रम सं.	कम्पनी का नाम	निवल लाभ (₹ करोड़ में)
1	ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड	20,926
2	एनटीपीसी लिमिटेड	12,619
3	कोल इंडिया लिमिटेड	9,794
4	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	6,615
5	एनएमडीसी लिमिटेड	6,342
6	इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड	5,005
7	पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड	4,420
8	साउथ ईस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड	4,300
9	पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड	4,234
10	महानदी कोलफील्डस लिमिटेड	4212
जोड़		**78,467**

यह देखा जा सकता है कि 10 सीपीएसईज़ ने 182 सीपीएसईज़ द्वारा कुल अर्जित लाभ का 53 प्रतिशत अंशदान किया। ब्याज और कर से पूर्व लाभ, लगाई गई पूंजी*, कर पश्चात लाभ, लाभांश, निवल सम्पत्ति#, निवल सम्पत्ति के प्रति कर-पश्चात लाभ का अनुपात, लगाई गई पूंजी के प्रति ब्याज और कर से पूर्व लाभ का अनुपात तथा इक्विटी के प्रति लाभांश को दर्शाने वाली 327 सरकारी कम्पनियों और निगमों का लाभकारिता विश्लेषण **परिशिष्ट VI** में दिया गया है।

- सीपीएसईज़ द्वारा घोषित लाभांश 2010-11 में ₹ 35,680 से बढ़कर 2012-13 में ₹ 49,929 करोड़ हो गया।
- 75 सरकारी कम्पनियों/निगमों ने 2012-13 में ₹ 18,631 करोड़ का लाभ कमाया परन्तु लाभांश की घोषणा नहीं की।
- भारत सरकार ने ₹ 2,25,053 करोड़ के निवेश पर ₹ 32,741 करोड़ का लाभांश प्राप्त किया।

1.3.2 सरकारी कम्पनियों और निगमों का लाभांश भुगतान

31 मार्च 2013 को समाप्त विगत तीन वर्षों के दौरान लाभांश की घोषणा करने वाली सरकारी कम्पनियों और निगमों की संख्या **परिशिष्ट VII** में दी गई है। 2012-13 में लाभांश की घोषणा करने

* लगाई गई पूंजी का मतलब है शेयर धारकों की निधियों एवं दीर्घकालिक उधारी से है।

निवल सम्पति का अर्थ है दत्त शेयर पूंजी का कुल योग और फ्रि रिजर्व और अधिशेष घटा संचित हानि और अस्थगित राजस्व व्यय फ्रि रिजर्व का अर्थ है सभी रिजर्व जो लाभ और शेयर प्रीमियम लेखे से सृजित हो किन्तु इसमें परिसम्पतियों के पुर्नमूल्यांकन से सृजित रिर्जव और मूल्यह्रास प्रावधान का राइट बैक सम्मिलित नहीं है।

वाले 107 सीपीएसईज़ (2 सांविधिक निगमों तथा 32 सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियों सहित) थे। इन सीपीएसईज़ द्वारा अर्जित निवल लाभ की प्रतिशतता के रूप में घोषित लाभांश 2010-11 में 33.34 *प्रतिशत* से बढ़ कर 2012-13 में 38.55 *प्रतिशत* हो गया। कुल मिलाकर, सीपीएसईज़ द्वारा 2012-13 में घोषित लाभांश 2010-11 में ₹ 35,680 करोड़ से ₹ 14,249 करोड़ तक बढ़कर 2012-13 में ₹ 49,929 करोड़ हो गया।

निवल लाभ और प्रदत्त पूंजी की तुलना में घोषित लाभांश

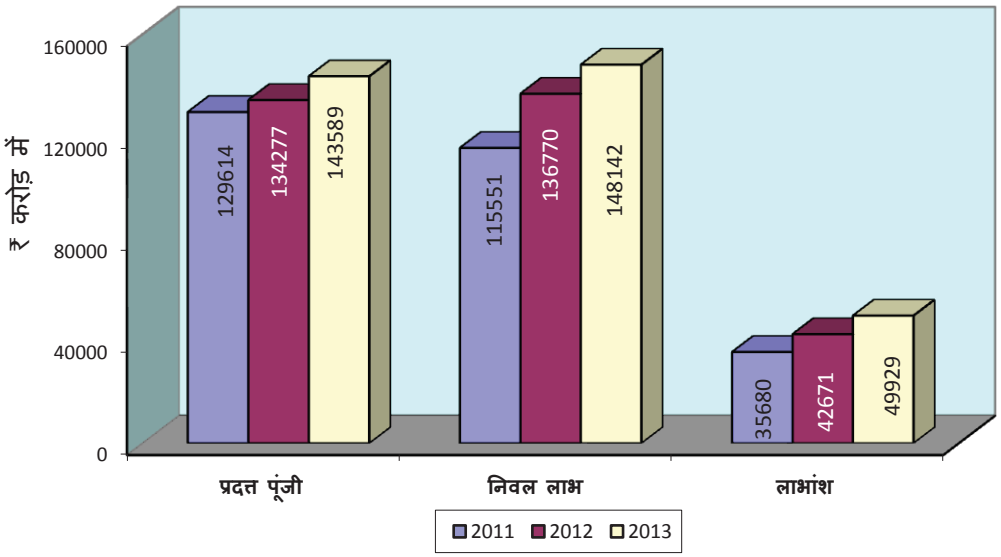

वर्ष 2012-13 के दौरान 182 सीपीएसईज़ जिन्होंने लाभ कमाया उनमें से केवल 107 सीपीएसईज़ ने लाभांश की घोषणा की थी। 75 सीपीएसईज़ (5 सूचीबद्ध कम्पनियों और एक सांविधिक निगम सहित) जिन्होंने ₹ 18,631 करोड़ का लाभ कमाया था और 2012-13 के दौरान लाभांश की घोषणा नहीं की, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

क्षेणी	कुल लाभ सीपीएसईज़ (सं.)	पीएसयूज़ जिन्होंने लाभ की घोषणा की				पीएसयूज़ जिन्होंने लाभ की घोषणा नहीं की		
		सीपीएसईज़ की संख्या	प्रदत्त पूंजी	निवल लाभ	घोषित लाभांश	सीपीएसईज़ की संखया	प्रदत्ता पूंजी	निवल लाभ
सांविधिक निगम	3	2	724.58	874.55	174.87	1	5,314.82	392.33
सूचीबद्ध कम्पनी	37	32	58,019.66	97,514.91	37,607.34	5	377.43	44.76
असूचीबद्ध कम्पनियां	142	73	41,701.15	31,121.98	12,146.97	69	37,451.38	18,193.56
जोड़	**182**	**107**	**1,00,445.39**	**1,29,511.44**	**49,929.18**	**75**	**43,143.63**	**18,630.65**

- चालू वर्ष में 107 सरकारी कम्पनियों और निगमों द्वारा घोषित ₹ 49,929 करोड़ के कुल लाभांश में से, भारत सरकार द्वारा प्राप्य लाभांश ₹ 32,741 करोड़* था। 327 सरकारी कम्पनियों और निगमों की इक्विटी पूंजी में भारत सरकार द्वारा किए गए ₹ 2,25,037 करोड़ के कुल निवेश पर प्रतिफल 14.55 प्रतिशत था। इसी प्रकार, 29 सरकारी कम्पनियों ने विभिन्न सरकारी कम्पनियों की इक्विटी में ₹ 4,482 करोड़ के दी गई पूंजी पर लाभांश के रूप में ₹ 9,403 करोड़ प्राप्त किए।
- पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन 10 सरकारी कम्पनियों ने ₹ 14,067 करोड़ का लाभांश घोषित किया जो 2012-13 में विभिन्न कम्पनियों द्वारा घोषित ₹ 49,929 करोड़ के कुल लाभांश का 28 प्रतिशत था।
- 1995 तथा 1996 में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों में यह परिकल्पित था कि लाभ कमाने वाली सभी कम्पनियां, जो अनिवार्यतः वाणिज्यिक उद्यम थे, या तो इक्विटी पर या कर-पश्चात् लाभ पर, जो भी अधिक हो, न्यूनतम 20 प्रतिशत लाभांश की घोषणा करेंगी। तेल, पेट्रोलियम, रसायन तथा अन्य आधारभूत क्षेत्रों में कम्पनियों द्वारा दिया जाने वाला न्यूनतम लाभांश कर-पश्चात् लाभ का 30 प्रतिशत था। तथापि, 30 कम्पनियाँ (4 सूचीबद्ध कम्पनियों सहित) जिन्होंने लाभांश घोषित किया था ने लाभांश की घोषणा करते समय संबंधित सरकारी निदेश का पालन नहीं किया, जैसा कि ***परिशिष्ट VIII*** में दिया गया है। इस के कारण कुल कमी 2012-13 में ₹ 3,588 करोड़ थी।
- मंत्रालय ने इस बात पर भी ज़ोर दिया था कि सरकार का उद्देश्य समूचे बोर्ड में सभी सरकारी कम्पनियों और निगमों में समग्र निवेश पर न्यूनतम पांच प्रतिशत प्रतिफल प्राप्त करना था। सभी सरकारी कम्पनियों और निगमों की इक्विटी में भारत सरकार द्वारा किए गए ₹ 2,25,037 करोड़ के कुल निवेश पर प्रतिफल ₹ 37,741 करोड़ अर्थात 14.55 *प्रतिशत* था।

1.3.3 मानी गई सरकारी कम्पनियों मे निवेश पर प्रतिफल

2010-11 से 2012-13 वर्षों के लिए मानी गई सरकारी कम्पनियों मे निवेश पर प्रतिफल के विवरण ***परिशिष्ट IV*** में दिए गए हैं। 137 मानी गई सरकारी कम्पनियों में से, 87 कम्पनियों ने ₹ 4,010 करोड़ का लाभ कमाया। इन 87 कम्पनियों में से, 39 ने ₹ 911 करोड़ का लाभांश घोषित किया जो उनकी ₹ 6,376 करोड़ की कुल प्रदत्त पूंजी का 14.29 प्रतिशत था। 2012-13 के दौरान 137 मानी गई सरकारी कम्पनियों में से 40 कम्पनियों ने ₹ 1,308 करोड़ की हानि उठाई। शेष दस कम्पनियों ने अभी तक वाणिज्यिक प्रचालन शुरू नहीं किए थे।

**** भारत सरकार द्वारा प्राप्त किया जाने वाला लाभांश सीधे केन्द्रीय सरकार के निवेश वाली 84 कम्पनियों से संबंधित था। बची हुई 23 कम्पनियां अन्य सरकारी कम्पनीं की सहायक कम्पनियां थी और उनमें भारत सरकार का प्रत्यक्ष निवेश नहीं था।***

1.3.3.1 2012-13 के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से 39 मानी गई सरकारी कम्पनियों द्वारा घोषित ₹ 911 करोड़ का लाभांश आया जैसाकि नीचे दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	कम्पनियों की सं.	प्रदत्त पूंजी	निवल लाभ	लाभांश
वित्तीय सेवाएं	25	3,675	1,708	662
विद्युत	2	1,229	280	135
बीमा	1	1,000	622	50
ठेका एवं निर्माण सेवाएं	1	250	176	35
परिवहन सेवाएं	1	164	30	20
व्यापार एवं विपणन	1	41	16	4
औद्योगिक विकास एवं तकनीकी परामर्श	6	16	25	3
खनिज एवं धातु	1	1	14	1
औद्योगिक विकास	1	1	1	1
जोड़	**39**	**6,377**	**2,872**	**911**

1.4 घाटे वाली सीपीएसईज़

घाटा उठाने वाली सीपीएसईज़ की संख्या 2010-11 में 83 सीपीएसईज़ से 2012-13 में 124 तक बढ़ गई। इस अवधि के दौरान इन सीपीएसई द्वारा उठाये गये घाटे में भी ₹ 22,246 करोड़ से ₹ 31,161 करोड़ की काफी वृद्धि हुई जिसका नीचे दी गई तालिका में विवरण है।

सूचीबद्ध/असूचीबद्ध वर्ष	घाटे वाली सीपीएसईज़* की संख्या	वर्ष का निवल घाटा	संचित घाटा	निवल सम्पत्ति
			(₹ करोड़ में)	
सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियां				
2010-11	9	5,082	13,608	-2,277
2011-12	8	7,089	15,503	-2,598
2012-13	14	11,439	20,810	6,420
असूचीबद्ध सरकारी कम्पनियों/निगम				
2010-11	74	17,182	52,641	77,647
2011-12	87	23,118	63,895	71,146
2012-13	110	19,722	58,889	54,278
जोड़				
2010-11	83	22,264	66,249	75,370
2011-12	95	30,207	79,398	68,548
2012-13	124	31,161	79,699	60,698

* फूड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया, इनलैंड वाटरवेज़ आथॉरिटी ऑफ इण्डिया तथा नेशनल हाइवेज़ अथॉरिटी ऑफ इण्डिया जिनके घाटे की भारत सरकार द्वारा सब्सिडी/अनुदान के रूप में प्रतिपूर्ति की जाती है, इस तालिका में शामिल नहीं हैं।

निम्नलिखित सीपीएसईज़ ने वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 500 करोड़ से अधिक का घाटा वहन किया।

क्र.सं.	कम्पनी का नाम	2012-13 में निवल हानि (₹ करोड़ में)
1	भारत संचार निगम लिमिटेड	7,884
2	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	5,321
3	चेन्नई पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड	1,767
4	हिन्दुस्तान केबिल्स लिमिटेड	885
5	मैंगलोर रिफाइनरी तथा पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	757

1.4.1 सरकारी कम्पनियों में पूंजी क्षरण

31 मार्च 2013 तक 135 सरकारी कम्पनियां और निगम थे जिनका संचित घाटा ₹ 92,908 करोड़ था। वर्ष 2012-13 के दौरान 135 सीपीएसईज़ में से 100 सीपीएसईज़ ने ₹ 19,559 करोड़ का घाटा उठाया तथा 35 सीपीएसईज़ ने वर्तमान वर्ष 2012-13 में घाटा नहीं उठाया तथापि ₹ 13,210 करोड़ का घाटा संचित था।

65 सरकारी कम्पनियों (135 में से) की निवल सम्पत्ति संचित घाटे द्वारा पूरी तरह क्षरित हो गई थी और निवल संपत्ति नकारात्मक थी। इन 65 कंपनियों में निवल संपत्ति 31 मार्च 2013 को ₹ 12,889 करोड़ के इक्विटी निवेश के प्रति ₹ (-) 68,202 करोड़ थी। इसमें 7 सूचीबद्ध कंपनियां शामिल है जिनकी निवल संपत्ति ₹ 2,422 करोड़ के इक्विटी निवेश के प्रति ₹ (-) 18,070 करोड़ थी। 65 कंपनियों जिनकी पूंजी क्षरित हुई थी, में से केवल 8 सीपीएसईज़ ने 2012-13 के दौरान ₹ 1,745 करोड़ का लाभ प्राप्त किया।

65 सीपीएसईज़ में से 29 जिनकी पूंजी क्षरित हुई थी, की बकाया सरकारी ऋण की राशि 31 मार्च 2013 को ₹ 16,115 करोड़ थी। इसमें ₹ 2,561 करोड़ के बकाया सरकारी ऋण वाली 4 सूचीबद्ध कंपनियां शामिल हैं।

संभावित रूग्णता दर्शाते हुए 259 सीपीएसईज़ जिनकी निवल संपत्ति सकारात्मक थी, में से 15 सीपीएसईज़ की निवल संपत्ति 31 मार्च 2013 के अंत में उनकी प्रदत्त पूंजी ₹ 12,109 करोड़ के आधे से कम थी।

1.5 सरकारी कम्पनियों की प्रचालन दक्षता

1.5.1 उत्पादन का मूल्य

तीन वर्ष की अवधि के दौरान कुल परिसम्पत्ति तथा लगाई गई पूंजी के प्रति उत्पादन के मूल्य को दर्शाने वाला सार ग्राफ नीचे दिया गया है:

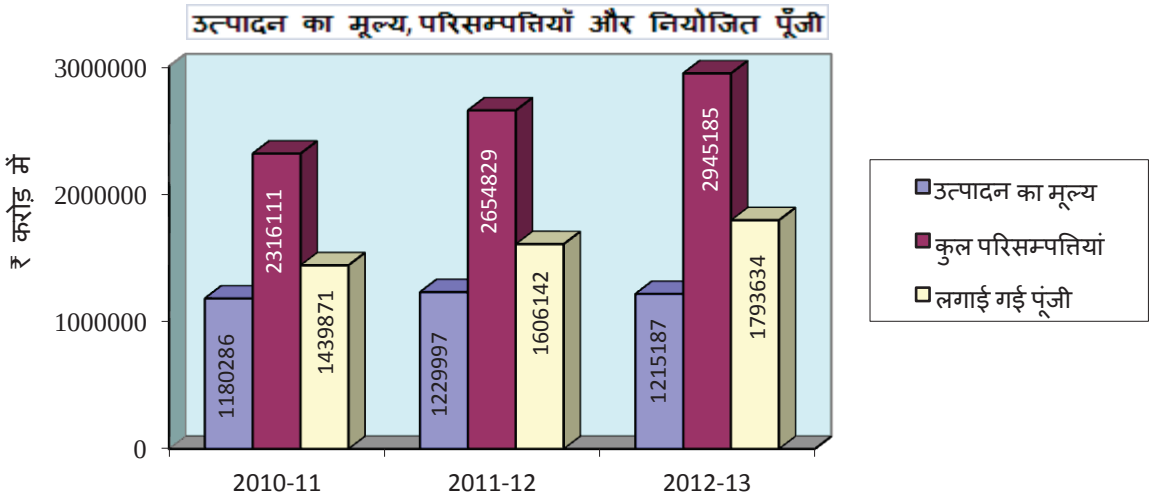

पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2012-13 में यद्यपि कुल परिसम्पत्ति और नियोजित पूंजी में वृद्धि थी तथापि उत्पादन के मूल्य में थोड़ी सी कमी हुई थी।

1.5.2 बिक्री एवं विपणन

2012-13 के दौरान 327 सीपीएसईज़ की कुल बिक्री ₹ 18,13,785 करोड़ थी। इनमें से 118 सीपीएसईज़ ने सरकारी विभागों को उनकी ₹ 9,45,238 करोड़ की निवल बिक्री के प्रति ₹ 2,03,376 करोड़ मूल्य की बिक्री की/सेवाएं प्रदान की। सरकारी क्षेत्र को उनकी कुल निवल बिक्री के संदर्भ में इन सीपीएसईज़ की बिक्री की समग्र प्रतिशतता 21.5 प्रतिशत परिकल्पित की गई।

67 सीपीएसईज ने ₹ 97,975 करोड़ का माल निर्यात किया अथवा विदेश में सेवाएं प्रदान की। यह उनकी ₹ 10,09,412 करोड़ की निवल बिक्री के प्रति 9.71 प्रतिशत परिकल्पित किया गया। 327 सीपीईज द्वारा की गई ₹ 18,13,785 करोड़ की कुल बिक्री के प्रति निर्यात बिक्री राशि 5.4 प्रतिशत थी। ₹ 1000 करोड़ से अधिक निर्यात बिक्री वाली सीपीएसईज़ निम्नलिखित हैं।

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	निर्यात बिक्री (₹ करोड़ में)
1	मंगलौर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	33,340
2	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	22,678
3	इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड	17,582
4	हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कोर्पोरेशन लिमिटेड	5,179
5	राष्ट्रीय एल्यूमीनियम कम्पनी लिमिटेड	3,410
6	पीईसी लिमिटेड	3,029
7	एमएमटीसी लिमिटेड	2,980
8	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	1,975
9	दि स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	1,563
10	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	1,188
जोड़		**92,924**

इन 10 सीपीएसईज की निर्यात बिक्री सभी सीपीएसईज के कुल निर्यात का 95% है।

1.5.3 अनुसंधान एवं विकास

निरन्तर वृद्धि के लिए विद्यमान उत्पादों को प्रोन्नत करने तथा नए उत्पाद, प्रक्रियाएं आदि विकसित करने के लिए प्रत्येक संगठन को अनुसंधान तथा विकास कार्य करने पड़ते हैं। 2012-13 के दौरान, 59 सीपीएसईज़ ने अनुसंधान और विकास पर ₹ 4,450 करोड़ लगाए। निम्नलिखित सीपीएसईज़ ने ₹ 100 करोड़ से अधिक का आर एंड डी व्यय किया:

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	कुल आर एंड डी व्यय (₹ करोड़ में)	निवल लाभ (₹ करोड़ में)	निवल लाभ के प्रति आरएंडडी व्यय की प्रतिशतता
1	हिन्दुस्तान एरोनोटिकल्स लिमिटेड	1,949	2,997	65
2	ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड	538	20,926	3
3	भारत इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	510	890	57
4	भारत हेवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड	337	6,615	5
5	इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड	249	5,005	5
6	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	148	2,400	6
7	एनटीपीसी लिमिटेड	102	12,619	1